

THE INTERNATIONAL OTT CONUNDRUM

OTT Regulatory policies differ from every country. Indian OTT segment also faces roadblocks which will be eased out soon. This article focusses on OTT policies across the globe.

INTERNATIONAL PRACTICES

The regulatory practices in respect of OTT services followed in some countries are outlined below.

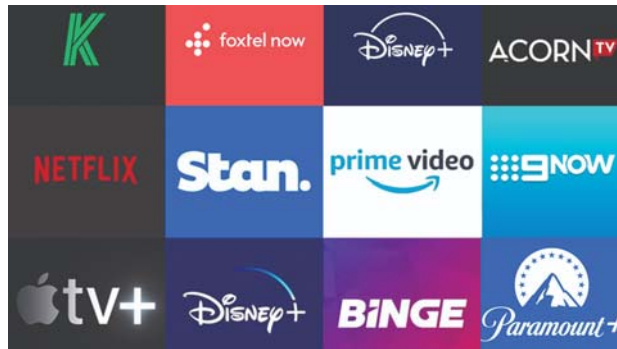
AUSTRALIA

In 2018, the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) conducted a study of the communication sector looking specifically at OTTs and the need for future access regulations.

The report concluded that, 'there is no basis for requiring equivalent regulatory treatment of OTT and traditional voice services'. The ACCC reasoned that 'the extent of substitution from traditional voice services to OTT voice services is limited by technical shortfalls (such as any-to-any connectivity) and consequently we do not consider OTT services to be full substitutes for voice services at this time.'

One of the findings of the report is that 'the competitive relationship between OTT services and the traditional communications services they replicate is likely to be different for each type of service. To the extent that competition from OTT services acts as a constraint on pricing, there may be a case for reducing or removing existing economic regulation of traditional communications services.'

In Australia, complete or nationwide internet shutdowns have not been reported. Certain websites or online platforms may be blocked or filtered to prevent access to illegal or harmful content, such as websites involved in the distribution of child pornography or extremist materials. The Australian government has also



अंतरराष्ट्रीय ओटीटी पहली

ओटीटी नियामक नीतियां हर देश की अलग-अलग हैं। भारतीय ओटीटी वर्ग को भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जिसे जल्दी ही दूर कर लिया जायेगा। यह लेख दुनियाभर में ओटीटी नीतियों पर केंद्रित है।

अंतरराष्ट्रीय प्रथायें

कुछ देशों में ओटीटी सेवा के संबंध में अपनायी जाने वाली नियामक प्रथाओं की रूपरेखा नीचे दी गयी है।

ऑस्ट्रेलिया

2018 में, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग (एसीसीसी) ने विशेष रूप से ओटीटी और भविष्य के पहुंच नियमों की आवश्यकताओं को देखते हुए संचार क्षेत्र का एक अध्ययन किया।

रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि 'ओटीटी और पारंपरिक वॉयस सेवाओं के समान नियामक उपचार की आवश्यकता का कोई आधार नहीं है। एसीसीसी ने तर्क दिया कि पारंपरिक वॉयस सेवाओं से ओटीटी वॉयस सेवाओं में प्रतिस्थापन की सीमा तकनीकी कमी (जैसे किसी से कहीं भी कनेक्टिविटी) द्वारा सीमित है और परिणामस्वरूप हम इस समय ओटीटी सेवाओं को वॉयस सेवाओं के लिए पूर्ण विकल्प नहीं मानते हैं।

रिपोर्ट के निष्कर्षों में से एक यह है कि 'ओटीटी सेवाओं और उनके द्वारा दोहराई जाने वाली पारंपरिक संचार सेवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा संबंध प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए अलग-अलग होने की संभावना है। इस हद तक की ओटीटी सेवाओं से प्रतिस्पर्धा मूल्य निर्धारण पर बाधा के रूप में कार्य करती है, पारंपरिक संचार सेवाओं के मौजूदा आर्थिक विनियमन को कम करने या हटाने का मामला हो सकता है।

ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण या राष्ट्रव्यापी इंटरनेट शटडाउन की सूचना नहीं मिली है। अवैध या हानिकारक सामग्री तक पहुंच को रोकने के लिए कुछ वेबसाइटों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक या फिल्टर किया जा सकता है, जैसे बाल पोर्नोग्राफी या चरमपंथी सामग्री के विवरण में शामिल

implemented measures to combat online piracy and copyright infringement, resulting in the blocking of specific websites. ISPs in Australia are required to comply with legal obligations and cooperate with law enforcement agencies when necessary.

AUSTRIA

The regulatory framework for electronic communications in Austria is set out in the Austrian Telecommunications Act 2021 (TKG), which transposed the Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (EECC) into Austrian Law.

The EECC introduced a new, broad definition of electronic communication services, which now includes:

- (a) Number based interpersonal communication services (hereinafter NB-ICS).
- (b) Number-independent interpersonal communication services (hereinafter NI-ICS) as defined in article 2 EECC.

The respective definitions in the Austrian TKG 2021 read as follows:

“Art 4 Definitions

‘number-based interpersonal communications service’ means an interpersonal communications service which connects with publicly assigned numbering resources, namely, a number or numbers in national or international numbering plans, or which enables communication with a number or numbers in national or international numbering plans;

‘number-independent interpersonal communications service’ means an interpersonal communications service which does not connect with publicly assigned numbering resources, namely, a number or numbers in national or international numbering plans, or which does not enable communication with a number or numbers in national or international numbering plans;“

With this new definition of “communications service” in the TKG 2021, many of the Internet-based services are in a direct competitive relationship with conventional telephony and SMS. Number-independent interpersonal communications services (NI-ICS) are now included in the

वेबसाइटों। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑनलाइन चोरी और कॉपीराइट उल्लंघन से निपटने के लिए उपाय भी लागू किये हैं जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट वेबसाइटों को अवरूद्ध कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में आईएसपी को कानूनी दायित्वों का पालन करना और आवश्यक होने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना आवश्यक है।

ऑस्ट्रिया

ऑस्ट्रिया में इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए नियामक ढांचा ऑस्ट्रियाई दूरसंचार दूरसंचार अधिनियम 2021 (टीकेजी) में निर्धारित किया गया है जिसने यूरोपीय संसद के निर्देश (ईयू) 2018/1972 और 11 दिसंबर 2018 की परिषद ने ऑस्ट्रियाई कानून में यूरोपीय इलेक्ट्रॉनिक संचार कोड (ईईसीसी) की स्थापना की।

ईईसीसी ने इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं की एक नयी, व्यापक परिभाषा पेश की, जिसमें अब शामिल है:

(ए) संख्या आधारित पारस्परिक संचार सेवायें (इसके बाद एनबी-आईसीएस)।

(बी) संख्या स्वतंत्र पारस्परिक संचार सेवायें (इसके बाद एनआई-आईसीएस) जैसाकि अनुच्छेद 2 ईईसीसी में परिभाषित किया गया है।

ऑस्ट्रियाई टीकेजी 2021 से संबंधित परिभाषायें इस प्रकार हैं: आर्टिकल 4 परिभाषा

नंबर आधारित पारस्परिक संचार सेवा का अर्थ एक पारस्परिक संचार सेवा से है जो सार्वजनिक रूप से निर्दिष्ट नंबरिंग संसाधनों से जुड़ती है, अर्थात् राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय नंबरिंग योजनाओं में एक संख्या या संख्या, या जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय नंबरिंग योजनाओं में किसी संख्या या नंबर के साथ संचार को सक्षम बनाती है।

नंबर स्वतंत्र पारस्परिक संचार सेवा का अर्थ एक पारस्परिक संचार सेवा है जो सार्वजनिक रूप से निर्दिष्ट नंबरिंग योजनाओं में किसी संख्या या संख्याओं से नहीं जुड़ती है या जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय नंबरिंग योजनाओं में किसी संख्या या संख्याओं के साथ संचार को सक्षम नहीं करता है।

टीकेजी 2021 में ‘संचार सेवा’ की इस नयी परिभाषा के साथ कई इंटरनेट आधारित सेवायें पारंपरिक टेलीफोनी और एसएमएस के साथ सीधे प्रतिस्पर्धी संबंध में हैं। संख्या स्वतंत्र पारस्परिक संचार सेवायें (एनआई-आईसीएस) अब कुछ क्षेत्र विशिष्ट नियमों के दायरे में शामिल हैं। टीकेजी 2021 उन्हें कुछ क्षेत्रों (कीवर्ड: समान खेल का मैदान) में पारंपरिक



scope of certain sector-specific regulations. The TKG 2021 places them on an equal footing with traditional communications services in some areas (keyword: "level playing field"), such as Security and integrity, Service Quality, Interoperability, Universal service fund, Objection procedures and procedural rules (Duty to notify contractual conditions), Information requirements and Monitoring of competition.

BANGLADESH

The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) has been empowered by the Government under the Bangladesh Telecommunication Regulation Act, 2001 (Act) to issue directives. Over-the-top (OTT) services are creating new dimensions in the entertainment industry and creating true substitution of the incumbent voice-based telecom services.

As a consequence, this phenomenon is asking for the overhaul of the regulatory regime telecom sector. Consideration of the economic impact of OTTs is based upon recognition of the fundamental differences between traditional telecommunication operators and OTTs, including inter-alia, control of broadband internet access, level of regulatory exposure, barriers to entry, competitive environment, level of substitutability between OTTs and traditional telecom services and interconnection to public networks.

Internet Protocol Telephony Service Provider (IPTSP) operators' OTT services shall be operated and regulated under the following existing policy, regulations and guideline:

- (i) International Long Distance Telecommunications Services (ILDTS) Policy 2010;
- (ii) IPTSP licensing Guidelines;
- (iii) Interconnection Regulations, 2004;
- (iv) Quality of service Regulations, 2018.

OTT means an application accessed and delivered over the public internet that may be a direct technical/functional substitute for traditional calling (& messaging) services. OTT user shall specifically refer to a user who is using a mobile based application to make a call (and/or send message) either to another OTT user or to a conventional subscriber (with a number) in PLMN/ PSTN/ IPTSP network.

संचार सेवाओं के साथ समानस्तर पर रखता है, जैसे सुरक्षा और अखंडता, सेवा गुणवत्ता, इंटरऑपरेबिलिटी, सार्वभौमिक सेवा निधि, आपत्ति प्रक्रियायें और प्रक्रियात्मक नियम (संविदात्मक शर्तें सूचित करने का कर्तव्य), सूचना आवश्यकतायें और प्रतिस्पर्धा की निगरानी।

बांग्लादेश

बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) को निर्देश जारी करने के लिए बांग्लादेश दूरसंचार विनियमन अधिनियम, 2001 (अधिनियम) के तहत सरकार द्वारा सशक्त बनाया गया है। ओवर-टॉप (ओटीटी) सेवायें मनोरंजन उद्योग में नये आयाम स्थापित कर रही हैं और मौजूदा आवाज आधारित दूरसंचार सेवाओं का वास्तविक प्रतिस्थापन कर रही हैं। परिणामस्वरूप यह घटना नियामक व्यवस्था दूरसंचार क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन की मांग कर रही है। परिणामस्वरूप यह घटना

नियामक व्यवस्था दूरसंचार क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन की मांग कर रही है। ओटीटी के आर्थिक प्रभाव पर विचार पारंपरिक दूरसंचार ऑपरेटरों और ओटीटी के बीच मूलभूत अंतरों की पहचान पर आधारित है, जिसमें अन्य बातों के अलावा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस का नियंत्रण, नियामक जोखिम का स्तर, प्रवेश में बाधाएँ, प्रतिस्पर्धी माहौल, ओटीटी के बीच प्रतिस्थापन का स्तर और पारंपरिक दूरसंचार सेवायें व सार्वजनिक नेटवर्क से इंटरकनेक्शन शामिल है।

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी सेवा प्रदाता (आईपीटीएसपी) ऑपरेटरों को ओटीटी सेवायें निम्नलिखित मौजूदा नीति, विनियमों और दिशा निर्देश के तहत संचालित और विनियमित की जायेंगी।

- (1) अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की संचार सेवायें (एलडीटीएस) नीति 2010
- (2) आईपीटीएसपी लाइसेंसिंग दिशा-निर्देश,
- (3) इंटरकनेक्शन विनियम 2004
- (4) सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2018

ओटीटी का मतलब सार्वजनिक इंटरनेट पर एक्सेस और वितरित किया जाने वाला एक आवेदन है जो पारंपरिक कॉलिंग (और मैसेजिंग) सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष तकनीकी/कार्यात्मक विकल्प हो सकता है। ओटीटी उपयोगकर्ता विशेष रूप से उस उपयोगकर्ता को संदर्भित करेगा जो किसी अन्य ओटीटी उपयोगकर्ता या पीएलएएमएन/पीएसटीएन/आईपीटीएसपी नेटवर्क में एक पारंपरिक ग्राहक (एक नंबर के साथ) को कॉल करने (और/या संदेश भेजने) के लिए मोबाइल आधारित आवेदन का उपयोग कर रहा है।



OTT (mobile app) based calling service (offered by nationwide IPTSP) is allowed into the PLMN and PSTN network, in accordance with Directives83 on Mobile Applications Based (Over-the-Top, OTT) Calling Services of the IPTSP.

BTRC will decide the specific interconnection capacity for IPTSP operators offering app-based calling service. Based on the considerations of different factors, BTRC will approve the interconnection capacity for individual service providers. The modality (technology) of the interconnection shall be decided by BTRC. For either type of technology (circuit or IP based), the IPTSP operator will provide an appropriate traffic monitoring system to the concerned division of BTRC.

OTT providers are required to have commercial negotiation with the infrastructure providers, for their services to be allowed through incumbent network. These commercial negotiations consider how much of the network resources of the incumbents is used for the particular OTT and the cost of the network resources. It is also considered whether the service offered by the OTT is a substitution to the core service offered by incumbent.

BRAZIL

In the current framework, there are services that do not require a licence as they are classified as a value-added service (serviço de valor adicionado, SVA). These services “complement” and “assist” telecommunication activities, and are considered neither telecommunication nor broadcasting services.

Over-the-top services (OTTs) are considered as Value-added services in Brazil. OTT services are not covered under any license and are not regulated in the country.

EUROPEAN UNION

The European Union (EU) has adopted the new European Electronic Communications Code (EECC) on the 11th of December 2018. The EECC is revising the framework to clearly regulate these new services. There are now two new regimes: one for number-independent service providers (such as instant messaging), the other for number-based service providers (such as VoIP). On the one hand, if OTT services offer access to publicly assigned numbering

आईपीटीएसपी के मोबाइल एप्लिकेशन आधारित (ओवर-टॉप, ओटीटी) कॉलिंग सेवाओं पर निर्देशों के अनुसार पीएलएमएन और पीएसटीएन नेटवर्क में ओटीटी (मोबाइल ऐप) आधारित कॉलिंग सेवा (देशव्यापी आईपीटीएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली) की अनुमति है।

वीटीआरसी ऐप आधारित कॉलिंग सेवा प्रदान करने वाले आईपीटीएसपी ऑपरेटरों के लिए विशिष्ट इंटरकनेक्शन क्षमता तय करेगा। विभिन्न कारकों के विचार के आधार पर, वीटीआरसी व्यक्तिगत सेवा

प्रदाताओं के लिए इंटरकनेक्शन क्षमताओं को मंजूरी देगा। इंटरकनेक्शन की पद्धति (तकनीकी) वीटीआरसी द्वारा तय की जायेगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी (सर्किट या आईपी आधारित) के लिए आईपीटीएसपी ऑपरेटर वीटीआरसी के संबंधित प्रभाग को उचित ट्रैफिक निगरानी प्रणाली प्रदान करेगा।

ओटीटी प्रदाताओं को मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से अपनी सेवाओं की अनुमति के लिए बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के साथ वाणिज्यिक बातचीत करने की आवश्यकता होती है। ये वाणिज्यिक वार्तायें इस बात पर विचार करती हैं कि पदधारियों के नेटवर्क संसाधनों का कितना उपयोग विशेष ओटीटी और नेटवर्क संसाधनों की लागत के लिए किया जाता है। यह भी विचार किया जाता है कि क्या ओटीटी द्वारा दी जाने वाली सेवा मौजूदा द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवा का प्रतिस्थापन है।

बाजील

वर्तमान ढांचे में ऐसी सेवायें हैं जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें मूल्य वर्धित सेवा (सर्विको डे वेलोर एडिसिओनाडो, एसवीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सेवायें दूरसंचार गतिविधियों को ‘पूरक’ और ‘सहायता’ करती हैं और इन्हें न तो दूरसंचार और न ही प्रसारण सेवायें माना जाता है।

बाजील में ओवर-टॉप (ओटीटी) सेवाओं को मूल्य वर्धित सेवाओं के रूप में माना जाता है। ओटीटी सेवायें किसी भी लाइसेंस के अंतर्गत नहीं आती हैं और देश में विनियमित नहीं हैं।

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ (ईयू) ने 11 दिसंबर 2018 को नये यूरोपीय इलेक्ट्रॉनिक संचार कोड (ईईसीसी) को अपनाया है। ईईसीसी इन नयी सेवाओं को स्पष्ट रूप से विनियमित करने के लिए ढांचे को संशोधन कर रहा है। अब दो नयी व्यवस्थायें हैं: एक संख्या स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं (जैसे तत्काल संदेश) के लिए, दूसरी संख्या आधारित सेवा प्रदाताओं (जैसे वीओआईपी) के लिए। एक ओर यदि ओटीटी सेवायें सार्वजनिक



resources, they are subject to similar rules as the traditional telecommunications operators. On the other hand, if they only offer “number-independent interpersonal communications services”, they will be subject to a new and lighter regime.

At first, this new set of obligations was supposed to be implemented in every EU country before the 21.12.2020. However, by October 2021 only eight countries (Finland, Hungary, Denmark, Greece, Bulgaria, France, Germany, and Italy) implemented the new framework in their national law.

The European Commission decided in April 2022 to refer Spain, Croatia, Latvia, Lithuania, Ireland, Poland, Portugal, Romania, Slovenia and Sweden to the Court of Justice of the European Union over their failure to fully transpose and communicate to the Commission how national measures transpose the EU Electronic Communications Code.

In July 2021, the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) published its ‘Guideline on Security Measures Under the EECC’ (4th Edition), confirming that the security provisions in the EECC for number-independent interpersonal communication services (NI-ICS) are the same as for the number-based services. The said guideline mentioned, inter alia, as below:

“SUPERVISION REGIME FOR NI-ICS PROVIDERS
In general, the security provisions in the EECC for NI-ICS are the same as for the number based services. Both are subject to (normal) ex-ante, supervision, and are required to provide information, submit to security audits and be subjected to investigation of non-compliance by the competent authorities. However, because these providers of do not normally exercise actual control over the transmission networks, there may be different risks for these providers, and certain security measures may not be needed, if justified on the basis of a risk assessment.”

FRANCE

France has implemented the EECC via an Ordinance published on the 26.05.2021 and two subsequent decrees issued in September and October 2021. As a result, it is now compulsory for VoIP and OTT operators to respect the obligations set out in the EECC.

रूप से निर्दिष्ट नंबरिंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है, तो वे पारंपरिक दूरसंचार ऑपरेटरों के समान नियमों के अधीन हैं। दूसरी ओर, यदि वे केवल ‘संख्या स्वतंत्र पारस्परिक संचार सेवायें’ प्रदान करते हैं तो वे एक नयी और हल्की व्यवस्था के अधीन होंगे।

सबसे पहले दायित्वों के इस नये सेट को 21.12.2020 से पहले प्रत्येक यूरोपीय संघ के देश में लागू किया जाना था। हालांकि अक्टूबर 2021 तक केवल आठ देशों (फिनलैंड, हंगरी, डेनमार्क, ग्रीस, बुल्गारिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली) ने अपने राष्ट्रीय कानून में नये ढांचे को लागू किया।

यूरोपीय आयोग ने अप्रैल 2022 में स्पेन, क्रोएशिया, लातविया, लिथुआनिया, आयरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया और स्वीडन को पूरी तरह से स्थानांतरित करने और आयोग को सूचित करने में उनकी विफलता के कारण यूरोपीय संघ के न्यायालय में भेजने का फैसला किया कि कैसे राष्ट्रीय उपाय ईयू इलेक्ट्रॉनिक संचार कोड को स्थानांतरित करते हैं।

जुलाई 2021 में यूरोपीय यूनियन एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी (ईएनआईएसए) ने ‘ईईसीसी के तहत सुरक्षा उपायों पर दिशानिर्देश (चौथा संस्करण) प्रकाशित किया, जिसमें पुष्टि की गयी कि संख्या स्वतंत्र पारस्परिक संचार सेवाओं (एनआई-आईसीएस) के लिए ईईसीसी में सुरक्षा प्रावधान संख्या आधारित सेवाओं के समान है। उपरोक्त दिशा निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

‘एनआई-आईसीएस प्रदाताओं के लिए पर्यवेक्षण व्यवस्था’ सामान्य तौर पर, एनआई-आईसीएस के लिए ईईसीसी में सुरक्षा प्रावधान संख्या आधारित सेवाओं के समान ही हैं। दोनों (सामान्य) पूर्व-पूर्व पर्यवेक्षण के अधीन हैं और उन्हें जानकारी प्रदान करना, सुरक्षा, ऑडिट प्रस्तुत करना और सक्षम अधिकारियों द्वारा गैर अनुपालन की जांच के अधीन होना आवश्यक है। हालांकि, क्योंकि ये प्रदाता आमतौर पर ट्रांसमिशन नेटवर्क पर वास्तविक नियंत्रण नहीं रखते हैं, इन प्रदाताओं के लिए अलग-अलग जोखिम हो सकते हैं और यदि जोखिम मूल्यांकन के आधार पर उचित ठहराया जाता है तो कुछ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

फ्रांस



फ्रांस ने 26.05.2021 को प्रकाशित एक अध्यादेश और सितंबर व अक्टूबर 2021 में दो आदेश जारी किये। परिणामस्वरूप अब वीओआईपी और ओटीटी ऑपरेटरों के लिए ईईसीसी में निर्धारित दायित्वों का सम्मान करना अनिवार्य है।

A press release by the French Regulator (ARCEP) in July 2022 mentioned that the transposition of the European Electronic Communications Code in May 2021 gave ARCEP newfound powers, including the regulation of new over-the-top (OTT) providers, which provide calling and instant messaging services, and updating the universal electronic communications service, to keep pace with the population's changing consumption habits.



जुलाई 2022 में फ्रांसीसी नियामक (एआरसीईपी) की एक प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि मई 2021 में यूरोपीय इलेक्ट्रॉनिक संचार कोड के स्थानांतरण ने एआरसीईपी को नयी शक्तियां प्रदान की, जिसमें नये ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्रदाताओं का विनियमन शामिल है, जो कॉलिंग प्रदान करते हैं और सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं को अपडेट करते हुए जनसंख्या में बदलती उपभोग आदतों के साथ तालमेल बनाये रखने के लिए तत्काल संदेश सेवायें शामिल हैं।

GERMANY

In 2019, there was a proposal for a new regulatory framework to monitor content on online platforms. A fully modernized Telecommunications Act (Telekommunikationsgesetz, TKG) has come into force in Germany on 1st December 2021. OTT-I providers are regulated under telecommunications law for the first time. OTT-I services facilitate individual and group communication in the form of language, images, videos, or other data using the internet protocol only over the open internet, without offering content.

In contrast, OTT-II services do not fall within the scope of Telecommunications Act. OTT-II services include content elements, ranging from search engines and on-demand platforms to information portals.

INDONESIA

To enhance legal certainty, especially with the rapidly developing digital platforms, the Ministry of Communication, and Informatics of the Republic of Indonesia (MOCI) has issued the Regulation regarding Private Electronic System Provider (Regulation) on 16th November 2020, which was promulgated and effective since 24th November 2020.

This Regulation is aimed to complete a regulatory framework regarding the management and supervision of electronic system providers by private entities (private ESPs). This Regulation provides clarification on the terms and requirements for registration, and most importantly removing data localization

जर्मनी

2019 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामग्री की निगरानी के लिए एक नियामक ढांचे का प्रस्ताव आया था। 1 दिसंबर 2021 को जर्मनी में एक पूरी तरह से आधुनिक दूरसंचार अधिनियम (टेलिकम्युनिकेशंसगेसेटज, टीकेजी) लागू हो गया है। ओटीटी-आई प्रदाताओं को पहली बार दूरसंचार कानून के तहत विनियमित किया गया है। ओटीटी-आई सेवायें सामग्री की पेशकश के बिना, केवल खुले इंटरनेट पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके भाषा, चित्र, वीडियो या अन्य डेटा के रूप में व्यक्तिगत और समूह संचार की



सुविधा प्रदान करती है।

इसके विपरीत, ओटीटी-2 सेवायें दूरसंचार अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं। ओटीटी-2 सेवाओं में सर्व ईजन और ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म से लेकर सूचना पोर्टल तक सामग्री तत्व शामिल है।

इंडोनेशिया

कानूनी निश्चितता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ, इंडोनेशिया गणराज्य के संचार और सूचना विज्ञान मंत्रालय (एमओसीआई) ने 16 नवंबर 2020 को निजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रदाता (विनियमन) के संबंध में विनियमन जारी किया है, जो 24 नवंबर 2020 से प्रख्यापित और प्रभावी है।

इस विनियमन का उद्देश्य निजी संस्थाओं (निजी ईएसपी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रदाताओं के प्रबंधन व पर्यवेक्षण के संबंध में एक नियामक ढांचे को पूरा करना है। यह विनियमन पंजीकरण के लिए नियमों और आवश्यकताओं पर स्पष्टीकरण प्रदान करता है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मसौदा विनियमन में पहले से पेश की गयी डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को हटाता है, जिससे



requirements previously introduced in the draft regulation which sparked controversies. The Regulation introduces an obligation.

The Regulation introduces an obligation (Article 3 (1) and (2) of the regulation) for private TSPs to be registered with the MOCI through the Online Single Submission (OSS) system. This obligation extends to all private TSPs that operate internet portals, websites, and applications used for specific purposes.

SINGAPORE

Infocomm Media Development Authority (IMDA) has taken a two-pronged approach to telecom licensing:

- (a) Facilities-based operators (FBO), which refers to the deployment and/or operations of telecom networks.
- (b) Service-based operators (SBO), which refers to utilizing telecom network elements from an FBO to provide telecom services.
 - (i) Individual SBO license, where individual licensing is required (Managed Data Network Service, MVNO, IX, IP Telephony, M2M etc).
 - (ii) Class SBO license, where only registration with IMDA is required (Interconnected VOIP, International Calling Cards, Call-back services etc).

Internet based Voice and Data Services (communications OTT service provider) must obtain a Service-Based Operating (SBO) licence that prescribes only a minimum quality of service standards. In contrast, TSPs require a Facilities-Based Operations licence, which have far greater regulatory obligations to fulfill than SBO licensees. They are required to pay higher licence fees and have roll out obligations to fulfill as per the license. They are also required to implement and support number portability; provide interconnection; pay for the use of radio frequencies and comply with the IMDA's Quality of Service standards.

The government has implemented measures to regulate online content and combat illegal activities, such

विवादों को जन्म दिया है। विनियमन एक दायित्व का परिचय देता है।

विनियमन निजी टीएसपी के लिए ऑनलाइन सिंगल सबमिशन (ओएसएस) प्रणाली के माध्यम से एमओसीआई के साथ पंजीकृत होने के लिए एक दायित्व (विनियमन के अनुच्छेद 3 (1) और (2) का परिचय देता है। यह दायित्व उन सभी निजी टीएसपी पर लागू होता है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाने वाले इंटरनेट पोर्टल, वेबसाइट और आवेदन संचालित करते हैं।

सिंगापुर

इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (आईएमडीए) ने दूरसंचार लाइसेंसिंग के लिए दोतरफा दृष्टिकोण अपनाया है:

(ए) सुविधा आधारित ऑपरेटर (एफबीओ), जो दूरसंचार नेटवर्क की तैनाती और/या संचालन को संदर्भित करता है।

(बी) सेवा आधारित ऑपरेटर (एसबीओ), जो दूरसंचार सेवायें प्रदान करने के लिए एफबीओ से नेटवर्क तत्वों का उपयोग करने को संदर्भित करता है।

(1) व्यक्तिगत एसबीओ लाइसेंस, जहां व्यक्तिगत लाइसेंस की आवश्यकता होती है (प्रबंधित डेटा नेटवर्क सेवा, एमवीएनओ, IX, आईपी टेलीफोनी, एम2एम आदि)

(2) क्लास एसबीओ लाइसेंस, जहां केवल आईएमडीए के साथ पंजीकरण आवश्यक है

(इंटरकनेक्टेड वीओआईपी, अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड, कॉल बैक सेवायें आदि)

इंटरनेट आधारित वॉयस और डेटा सेवाओं (संचार ओटीटी सेवा प्रदाता) को एक सेवा आधारित ऑपरेटिंग (एसबीओ) लाइसेंस प्राप्त करना होगा जो केवल सेवा मानकों की न्यूनतम गुणवत्ता निर्धारित करता है। इसके विपरीत टीएसपी की सुविधा आधारित संचालन लाइसेंस की आवश्यकता होती है जिसे पूरा करने के लिए एसबीओ लाइसेंसधारियों की तुलना में कहीं अधिक नियामक दायित्व होते हैं। उन्हें अधिक लाइसेंस फीस का भुगतान करना पड़ता है और लाइसेंस के अनुसार रोल आउट दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। उन्हें नंबर पोर्टेबिलिटी को लागू करने और उसका समर्थन करने की भी आवश्यकता है, इंटरकनेक्शन प्रदान करना, रेडियो फ्रीक्वेंसी के उपयोग के लिए भुगतान करें और आईएमडीए के सेवा गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करें।

सरकार ने ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने और फर्जी समाचार, घृणास्पद भाषण या ऑनलाइन घोटालों के प्रसार जैसी अवैध



as the spread of fake news, hate speech, or online scams. These measures involve targeted actions against specific websites or online platforms that violate local laws or regulations. In some cases, access to certain websites or content may be restricted or blocked temporarily. Singapore has strict regulations in place to maintain social harmony and national security, which may involve monitoring or restricting certain online activities. However, complete or nationwide internet shutdowns have not been reported in Singapore.

TRINIDAD AND TOBAGO

The topic of OTTs was first considered by the Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago (TATT) in its consultative document, "Towards the Treatment of Over-the-Top (OTT) Services" in June 2015. In addition to evaluating the impact of OTT voice over Internet Protocol (VoIP) services within the industry, the document also aimed to engage the public on pertinent issues relating to OTTs. At that time, the TATT Authority took the decision to subsume previous discussions on OTT issues and net neutrality into one document addressing both topics.

In July 2018, the TATT Authority began public stakeholder discussions on the topics of net neutrality and OTT regulation through its consultative document Discussion Paper on Net Neutrality and OTT Services in Trinidad and Tobago (the Discussion Paper). The Authority sought feedback on the document from stakeholders with respect to the proposed guiding principles and regulatory approaches to net neutrality and the treatment of OTT services in Trinidad and Tobago.

In October 2021, the Authority published the decisions on recommendations (DORs) and the final version of the Discussion Paper. Based on feedback from that consultation process, and considering the dynamism of the industry, TATT indicated that future consultations on both topics would continue in separate frameworks on net neutrality and OTTs.

TATT has signaled some interest in introducing regulations to explicitly govern OTT services, particularly those which function equivalently or similarly to the traditional services and use numbering resources to connect to the PSTN.

TATT published "Framework on Over-the-Top

गतिविधियों से निपटने के लिए उपाय लागू किया है। इन उपायों में स्थानीय कानूनों या विनियमों का उल्लंघन करने वाली विशिष्ट वेबसाइटों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई शामिल है। कुछ मामलों में कुछ वेबसाइटों या सामग्री तक पहुंच अस्थायी रूप से प्रतिबंधित या अवरुद्ध की जा सकती है। सिंगापुर में सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाये रखने के लिए सख्त नियम हैं जिसमें कुछ ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी या प्रतिबंधित करना शामिल हो सकता है। हालांकि सिंगापुर में पूर्ण या राष्ट्रव्यापी इंटरनेट शटडाउन की सूचना नहीं मिली है।

त्रिनिदाद और टोबैगो

ओटीटी के विषय पर पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो के दूरसंचार प्राधिकरण (टीएटीटी) ने जून 2015 में अपने परामर्शी दस्तावेज 'टुवर्ड्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर-टॉप (ओटीटी) सर्विसेज में विचार किया था। उद्योग के भीतर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) सेवाओं पर ओटीटी वॉयस के प्रभाव का मूल्यांकन करने के अलावा, दस्तावेज का उद्देश्य ओटीटी से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर जनता को शामिल करना भी है। उस समय, टीएटीटी प्राधिकरण ने ओटीटी मुद्दों और नेट तटस्थता पर पिछली चर्चाओं को दोनों विषयों को संबोधित एक दस्तावेज में समाहित करने का निर्णय लिया।

जुलाई 2018 में, टीएटीटी प्राधिकरण ने त्रिनिदाद और टोबैगो में नेट तटस्थता और ओटीटी सेवाओं पर अपने परामर्शी दस्तावेज चर्चा पत्र (चर्चा पत्र) के माध्यम से नेट तटस्थता और ओटीटी विनियमन के विषयों पर सार्वजनिक हितधारक चर्चा शुरू की। प्राधिकरण ने नेट तटस्थता और त्रिनिदाद और टोबैगो में ओटीटी सेवाओं के उपचार के लिए प्रस्तावित मार्गदर्शक सिद्धांतों और नियामक दृष्टिकोण के संबंध में हितधारकों से दस्तावेज पर प्रतिक्रिया मांगी।

अक्टूबर 2021 में, प्राधिकरण ने सिफारिशों पर निर्णय (डीओआर) और चर्चा पत्र का अंतिम संस्करण प्रकाशित किया। उस परामर्श प्रक्रिया पर मिले फीडबैक के आधार पर और उद्योग की गतिशीलता पर विचार करते हुए, टीएटीटी ने संकेत दिया कि दोनों विषयों पर भविष्य में परामर्श नेट तटस्थता और ओटीटी पर अलग-अलग ढांचे में जारी रहेगा।

टीएटीटी ने ओटीटी सेवाओं को स्पष्ट रूप से नियंत्रित करने के लिए नियमों को पेश करने में कुछ रुचि का संकेत दिया है, विशेष रूप से वे जो पारंपरिक सेवाओं के बराबर या समान रूप से कार्य करते हैं और पीएसटीएन से जुड़ने के लिए नंबरिंग संसाधनों का उपयोग करते हैं।

टीएटीटी ने परामर्श के पहले दौर के लिए अगस्त 2022 में



Services (OTTs) in Trinidad and Tobago” in August 2022 for a first round of consultation. In the proposed framework, TATT defines Over the Top Services as “Content, service or application, accessed by the public via the Internet, that may be a direct substitute for, and/or may compete with a public telecommunications and/or broadcasting service.” and that the scope of the proposed Framework is limited to OTT communications (voice and messaging) and OTT media services. This Framework presents TATT’s recommendations on the treatment of OTT services accessed in Trinidad and Tobago.

TURKEY

Within the scope of the Mobile Call Termination market, it was evaluated that in Turkey, OTT messaging services, generally put some degree of competitive strain on mostly SMS/MMS services. In this regard, the tariff control obligation on SMS/MMS termination was lifted for mobile network operators. The licenced operators in Turkey complain about the OTTs that these providers are not regulated and should be regulated like licensed operators.

The amending law, passed and published on 13 October 2022 defines OTT services and OTT service provider as below:

“Over the top service: electronic communication services between persons within the scope of auditory, written, visual communication that are provided through a publicly available software independent of operators or the internet service provided to subscribers and users who have internet access.

Over the top service provider: Natural persons or legal entities providing services that are covered by the definition of over the top services.”

The law gives a clear power to The Information and Communication Technologies Authority (ICTA) (Turkish: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)) to regulate and authorize OTT service providers considering the

त्रिनिदाद और टोबैगो में ‘ओवर-द-टॉप सर्विसेज (ओटीटी) पर फ्रेमवर्क प्रकाशित किया। प्रस्तावित ढांचे में टीएटीटी ओवर द टॉप सेवाओं को ‘इंटरनेट के माध्यम से जनता द्वारा एक्सेस की गयी सामग्री, सेवा या आवेदन के रूप में परिभाषित करता है, जो सार्वजनिक दूरसंचार और/या प्रसारण सेवा का प्रत्यक्ष विकल्प हो सकता है और/या उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और प्रस्तावित ढांचे का दायरा ओटीटी संचार (वॉयस और संदेश) और ओटीटी मीडिया सेवाओं तक सीमित है। यह फ्रेमवर्क त्रिनिदाद और टोबैगो में एक्सेस की गयी ओटीटी सेवाओं के उपचार पर टीएटीटी की सिफारिशों को प्रस्तुत करता है।

तुर्की

मोबाइल कॉल टर्मिनेशन बाजार के दायरे में, यह मूल्यांकन किया गया कि तुर्की में ओटीटी मैसेजिंग सेवायें आमतौर पर ज्यादातर एसएमएस/एमएमएस सेवाओं पर कुछ हद तक प्रतिस्पर्धी दबाव डालती हैं। इस संबंध में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के लिए एसएमएस/एमएमएस समाप्ति पर टैरिफ नियंत्रण दायित्व हटा दिया गया था। तुर्की में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओटीटी के बारे में शिकायत करते हैं कि ये प्रदाता विनियमित नहीं हैं और इन्हें लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों की तरह विनियमित किया जाना चाहिए।

13 अक्टूबर 2022 को पारित और प्रकाशित संशोधित कानून ओटीटी सेवाओं और ओटीटी सेवा प्रदाता को

निम्नानुसार परिभाषित करता है:

‘ओवर द टॉप सेवा, ऑडिटी, लिखित, दृश्य संचार के दायरे में व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवायें जो ऑपरेटरों से स्वतंत्र सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर या इंटरनेट एक्सेस वाले ग्राहकों और उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवा के माध्यम से प्रदान की जाती है।’

ओवर द टॉप सेवा प्रदाता: प्राकृतिक व्यक्ति या कानूनी संस्थायें जो सेवायें प्रदान करती हैं जो ओवर द टॉप सेवाओं की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं।

कानून सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण (आईसीटीए) (तुर्की: विल्ली टेक्नोलोजिलेरी वे इलेटिसिम कुरुमु (बीटीके)) को ओटीटी की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ओटीटी सेवा प्रदाताओं को विनियमित और अधिकृत करने की स्पष्ट शक्ति देता है। हालांकि वर्तमान



characteristics of the OTTs. However, currently BTK is closely monitoring the practices of the other countries, and possible regulation proposals will be evaluated in the near future.

UNITED STATES OF AMERICA

Non-interconnected OTT communications apps are not regulated as telecommunications services under US communications Act.

The US distinguishes between 'telecommunications services' (e.g. voice telephony) and 'information services' (e.g. text messaging). Telecommunications services are regulated more heavily than information services.

The US Congress has found that the 'Internet and other interactive computer services have flourished, to the benefit of all Americans, with a minimum of government regulation'.

Under US law, the policy of the US is 'to preserve the vibrant and competitive free market that presently exists for the Internet and other interactive computer services, unfettered by Federal or State regulation.'

While the United States has not experienced a complete internet shutdown, there have been instances where specific websites or online services have been temporarily restricted or blocked. These actions are usually taken for reasons related to national security or during periods of emergency. ■

में वीडियो के अन्य देशों की प्रथाओं की बरीकी से निगरानी कर रहा है और निकट भविष्य में संभावित विनियमन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जायेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका

नॉन इंटरकनेक्टेड ओटीटी संचार ऐप्स को अमेरिका संचार अधिनियम के तहत दूरसंचार सेवाओं के रूप में विनियमित नहीं किया जाता है।

अमेरिकी दूरसंचार सेवाओं (जैसे वॉयस टेलीफोनी) और सूचना सेवाओं (जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग) के बीच अंतर करता है। दूरसंचार सेवाओं को सूचना सेवाओं की तुलना में अधिक सख्ती से विनियमित किया जाता है।

अमेरिकी कांग्रेस ने पाया है कि न्यूनतम सरकारी विनियमन के साथ सभी अमेरिकियों के लाभ के लिए इंटरनेट और अन्य इंटरैक्टिव कंप्यूटर सेवायें फली-फूली हैं।

अमेरिकी कानून के तहत अमेरिका की नीति 'संघीय या राज्य विनियमन से मुक्त, इंटरनेट और अन्य इंटरैक्टिव कंप्यूटर सेवाओं के लिए वर्तमान में मौजूद जीवंत और प्रतिस्पर्धा मुक्त बाजार को संरक्षित करना है।

हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्ण इंटरनेट शट डाउन का अनुभव नहीं किया है लेकिन

ऐसे उदाहरण हैं जहां विशिष्ट वेबसाइटों या ऑनलाइन सेवाओं को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित या अवरूद्ध किया गया है। ये कार्रवाइयां आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कारणों से या आपातकाल की अवधि के दौरान की जाती हैं। ■












**INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY**



MAGAZINE

**... You Know What You are doing
But Nobody Else Does**

ADVERTISE NOW!

Contact: Mob.: +91-9108208956

Tel.: +91-22-6216 5313

Email: geeta.lalwani@nm-india.com